



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092023-248850
CG-DL-E-20092023-248850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2023/भाद्र 29, 1945

No. 224]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023/BHADRA 29, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2023

मामला सं. एडी (ओ.आई.) - 13/2023

विषय: चीन जन. गण. से "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/13/2023- डीजीटीआर.—क. पृष्ठभूमि

1. 'टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर्स' (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है), और कई अन्य निर्माता के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए "हार्डहोप फर्नीचर फिटिंग्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएट्स प्रा. लि." (जिसे यहां आगे "हार्डहोप" भी कहा गया है), से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण भारत में उद्योग को क्षति हो रही है।
2. प्राधिकारी एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) ए डी नियमावली के नियम 5 के उप नियम 4 के अनुसार टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का संज्ञान लेते हैं।

3. प्राधिकारी को पिछले चार वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तु के आयात आंकड़े भी प्राप्त हुए हैं जो चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि दर्शाते हैं। चीन जन. गण. से आयात संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का 85.24 प्रतिशत है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर्स” है, जिसे ड्रावर रनर्स/चैनल/ साफ्ट क्लोज टेलीस्कोपिक चैनल के रूप में भी जाना जाता है। इसे आम तौर पर ड्रावर में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वस्तुओं को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। यह एक छोटा सा यंत्र होता है, जो ड्रावर को बंद करते और खोलते समय उसकी गति को सरल बनाने में मदद करता है। टेलीस्कोपिक चैनल या रनर आधुनिक फर्नीचर डिजाइन का एक अनिवार्य घटक है जो ड्रावर की कार्यक्षमता और सुन्दरता को बढ़ा देता है।
5. इसमें दो या उससे अधिक इंटरलॉकिंग मेटल सेक्शन होते हैं जो ड्रावर के खुलने और बंद होने पर फैलते और सिकुड़ते हैं। टेलीस्कोपिक चैनल या रनल को आम तौर पर फर्नीचर, कैबिनेट और ऐसे उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जिनकी भंडारण स्थान पर सरल पहुंच होती है।
6. यद्यपि इस उत्पाद को अनेक प्रकार के विभिन्न आकारों और प्रकारों में उत्पादित किया और बेचा जाता है। तथापि, ये अनिवार्य रूप से भार के अनुसार तुलनीय हैं। उत्पाद के आकार में परिवर्तन उत्पादन की इकाई लागत और बिक्री कीमत (भार के आधार पर) में वास्तव में कोई बदलाव नहीं करता है।
7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 83 के तहत उपशीर्षक 83024110, 83024190, 83024200 और 83024900 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच पर बाध्यकारी नहीं है।
8. हितबद्ध पक्षकारों को इस अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे संबंधी टिप्पणियां करने का निर्देश दिया गया है।

ग. समान वस्तु

9. हार्डहोप के दावे को नोट करते हुए प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ नियमावली के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग बिखरा हुआ है और पूरी तरह एम एस एम ई श्रेणी से संबंधित है। रिकॉर्ड में सूचना यह दर्शाती है कि भारत में 30 ज्ञात उत्पादकों में से हार्डहोप लगभग 25 घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः प्राधिकारी इस बात से प्रथमदृष्टया संतुष्ट हैं कि यह अभ्यावेदन नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।
11. इसके अलावा, एमएसएमई और उद्योग की खंडित प्रकृति, इसमें शामिल उत्पादकों की संख्या पर विचार करते हुए, प्राधिकरण, व्यापार नोटिस 09/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के संदर्भ में, व्यापार नोटिस में निर्दिष्ट अनुबंधों के अनुसार घरेलू उत्पादकों से जानकारी मांगता है, जिसके आधार पर प्राधिकरण चोट मार्जिन के निर्धारण के लिए घरेलू उत्पादकों का नमूना लेगा। इसलिए, जबकि घरेलू उद्योग के सभी उत्पादकों से संबंधित जानकारी को क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया जाएगा, गैर-हानिकारक कीमत और क्षति मार्जिन एक नमूने के डेटा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

ङ. कथित पाटन का आधार

12. प्राधिकारी की प्रक्रिया पर विचार करते हुए और चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार यह माना गया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाना चाहिए कि अनुच्छेद 15 क(i) के प्रावधानों के अनुसार समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पाद और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, चीन की कीमतों या लागतों को जांच के अधीन उद्योग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी

लागत और कीमत की जानकारी बाजार संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

13. चूंकि (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत, (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य, (ग) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत संबंधी सूचना इस स्तर पर प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का अनुमान कच्ची सामग्री की लागत, सुविधाओं की लागत और घरेलू उत्पादकों द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन करके उत्पादन लागत के आधार पर लगाया गया है।
14. निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यात कीमत सीआईएफ मूल्य पर आधारित हैं जबकि सामान्य मूल्य कारखाना द्वार स्तर पर हैं, निर्यात कीमत को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन आदि के लिए समायोजित किया गया है।
15. तदनुसार, ऊपर यथापरिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जो दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिनों का अनुमान निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

च. कथित क्षति का आधार

16. प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग को समग्र रूप से और सापेक्ष रूप से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति हो रही है। आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि भारतीय उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है जिससे घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। इसके अलावा, सूचना यह भी दर्शाती है कि मांग में वृद्धि के बावजूद भारतीय उद्योग के उत्पादन में भारी गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप अत्यंत कम उपयोग स्तर रहे हैं। यद्यपि, आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव संबंधी पूरी सूचना इस स्तर पर प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, तथापि, प्राप्त सूचना के आधार पर फिर भी यह देखा गया है कि उद्योग को लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव से भी नुकसान उठाना पड़ा है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

17. प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे नियमावली भी कहा गया है) के नियम 5(4) के अनुसार हार्डहोप द्वारा प्रदत्त सूचना और डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों का संज्ञान लेते हैं जिनमें निम्नानुसार बताया गया है /

“उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वतः कोई जांच शुरू कर सकते हैं, यदि वह” सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त [सीमाशुल्क आयुक्त] से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से इस बात से संतुष्ट हैं कि उप नियम (3) के खंड (ख) में उल्लिखित स्थितियों की मौजूदगी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं।

18. एडी नियमावली नियम 5(4) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी चीन जन.गण. से “टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर” के आयातों के संबंध में स्वतः एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि

19. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है तथा क्षति अवधि में 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. संबद्ध देश

20. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ञ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
23. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 22 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली, के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार के लिए नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. “गोपनीय” और “अगोपनीय” अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश

संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी टिप्पणी कर सकते हैं।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

ण. असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2023

(Case No. OI-13/2023)

Subject: Initiation of Anti-dumping Investigation concerning imports of “Telescopic Channel Drawer Slider” from China PR.

F. No. 6/13/2023-DGTR.—A. Background

1. A representation has been received from (“Highhope Furniture Fittings Manufacturers Associates Pvt Ltd ” (hereinafter referred to as “Highhope”), and several other manufacturers representing manufacturers of “Telescopic Channel Drawer Sliders” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) stating that the industry in India is getting injured in view of increase in dumped imports of the subject goods from China PR (hereinafter referred to as subject country).
2. The Authority hereby takes cognizance of the information provided by the Indian industry manufacturing telescopic channel drawer sliders as per sub-rule 4 of rule 5 of Customs Tariff (identification Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”) AD rules.
3. The Authority has also received the import data of the subject goods during the past four years which indicates increased imports from China PR. Imports from China PR accounts for 85.24% of the total imports of the subject goods.

B. Product under consideration

4. The product under consideration in the preset investigation is “telescopic channel drawer slider”, also known as a drawer runner/channel/soft close telescopic channel. It is generally used in drawers, which are used for storing things. It is a small device that helps to simplify fluid motion while the drawer is closed and opened. Telescopic channels or runners are an essential component of modern furniture design that enhance the functionality and aesthetics of drawers.
5. It consists of two or more interlocking metal sections that extend and retract as the drawer is opened and closed. Telescopic channels or runners are commonly used in furniture, cabinets, and appliances that require easy access to storage space.
6. While the product is produced and sold in a number of different size and varieties, essentially these are comparable in terms of weight. The change in size of the product does not materially alter the unit cost of production and selling price (on weight basis).
7. The product under consideration is classified under Chapter 83 of the Customs Tariff Act under subheading 83024110, 83024190, 83024200, and 83024900. The customs classification is only indicative, and not binding on the scope of this investigation.
8. The interested parties are directed to make comments on the scope of product under consideration within 15 days of this initiation notification.

C. Like Article

9. Noting the claim of the Highhope, the Authority *prima facie* holds that the goods produced by the domestic industry and the goods imported from subject country are comparable and also technically and commercially substitutable. Goods produced by the Indian industry are *prima facie* being treated as “like article” to the product under consideration under the Rules for the purpose of the present investigation.

D. Domestic industry and standing

10. The Authority notes that the Indian industry is fragmented in nature, and belongs to the MSME category. Information on record shows that out of 30 known producers in India, Highhope represents about 25 domestic producers. Therefore, the Authority is *prima facie* satisfied that representation has been made 'by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.
11. Further, considering the MSME and fragmented nature of the industry, the number of producers involved, the Authority, in terms of Trade Notice 09/2021 dated 29th July 2021, seeks information from domestic producers as per Annexure I referred to in the trade notice based on which Authority shall undertake sampling of domestic producers for the purpose of determination of injury margin. Therefore, while the information concerning all producers constituting domestic industry will be considered for injury analysis, the non-injurious price and injury margin will be determined based on data of a sample.

E. Basis of alleged dumping

12. Considering the practise of the Authority and as per Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol it is considered that the Chinese producers must be asked to demonstrate that consistent with the provisions of Article 15(a)(i), market economy conditions prevail in the industry producing the like product, with regard to the manufacture, production and sale of that product under consideration. In case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value may be calculated in terms of provisions of Para 7 of Annexure I to the Rules.
13. Since, information on (a) the price in a market economy third country; (b) constructed value in a market economy third country; (c) the price from such a third country to other country, including India, is not available with the Authority at this stage, therefore, normal value in the subject country has been estimated on the basis of cost of production; taking into account cost of raw material, cost of utilities and conversion cost of domestic industry based on representations made by the domestic producers, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.
14. For determination of export price, the Authority has considered transaction wise import data procured from DGCI&S. The export prices have been adjusted for port expenses, bank charges, inland freight, commission etc. to determine the ex-factory export price based on best available information.
15. Accordingly, based on the normal value and export price as computed above, there is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

F. Basis of alleged injury

16. Based on information available with the Authority, it is prima facie noted that the Indian industry is getting injured as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms and in relative terms. The market share of imports have increased whereas that of the Indian industry has declined. Imports appear to undercut the price of the domestic industry thereby causing price suppression and depression in the domestic market. Further, information also indicates that despite increasing demand, production of the Indian industry has declined significantly, resulting in low-capacity utilisation. While complete information on impact on economic parameters is not available with the Authority at this stage, it is nonetheless observed based on information received that the industry has also suffered an adverse impact on profitability.

G. Initiation of Anti-dumping Investigation

17. The Authority takes cognizance of information provided by Highhope and the DGCI&S import data as Rule 5(4) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules) states as under:

“Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the designated authority may initiate an investigation suo motu if it is satisfied from the information received from the [Commissioner of Customs] appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or from any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances referred to in clause (b) of sub-rule (3)”

18. Keeping in view the rule 5(4) of the AD Rules, the Authority initiates a suo motu Anti-dumping Investigation on imports of “Telescopic Channel Drawer Slider” from China PR.

H. Period of Investigation

19. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months) and the injury period will cover the periods 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 and the POI.

I. Subject Country

20. The subject country involved in the present investigation is China PR.

J. Procedure

21. Principles as given in Rule 6 of the Rules shall be followed for the present investigation.

K. Submission of Information

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
23. The known producers/ exporters in the subject country, the Government through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 22 above.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
30. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

36. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

O. Non-cooperation

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority